(ग) गन्ने की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि के दौरान 21 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में "गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास" की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ।

मछली पकड़ने वाले पुराने जलयान

2761. **श्री आस मोहम्मद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में मछली पकड़ने वाले जलयान बहुत पुराने हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार ने मछली पकड़ने वाले आधुनिक जलयान प्राप्त करने हेतु अभी तक क्या प्रयास किये है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1992-93 के अन्त तक देश में मछली पकड़ने वाले 25,500 यंत्रीकृत जलयान, मछली पकड़ने वाली 25,500 मोटर लगी नौकायें तथा 1,72,000 पारम्परिक (गैर-यंत्रीकृत) नौकाये थी। इसके अतिरिक्त, संयुक्त उद्यमों / पट्ट की व्यवस्थाओं के अंतर्गत वर्तमान में वास्तविक रूप से प्रचालन में 19 जलयानों के अलावा गहरे समुद्र में झींगा पकड़ने वाले लगभग 180 जलपोत संचालित किए जा रहे थे। सरकार की नीति पारम्परिक नौकाओं के यंत्रीकरण मोटरीकरण को प्रोत्साहन देने की रही है जिससे अधिक दूर तक समुद्री यात्रा की क्षमता बढती है तथा परिणामस्वरूप मछवारे अधिक मछली पकड़ते है और उनकी अधिक आय होती है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों को प्रोत्साहन देने की नीति है ताकि गहरे समुद्र के मत्स्यन संसाधकों का, देश में समुद्रीय मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने में प्रयोग किया जा सके जो कि इस समय किसी महत्वपूर्ण सीमा तक उपयोग में नहीं लाए जा रहे है ।

(ग) सरकार द्वारा समुद्रीय मत्स्यन क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए उठाये गये कुछ बड़े कदमों में संचालन के क्षेत्र का विस्तार 50 मीटर की गहराई से अधिक तक करने के लिए मछली पकड़ने वाली पारम्परिक नौका का मोटरीकरण, शार्क, ट्रूना आदि के लिए बहु-अवसर मध्यवर्ती किस्म के समुद्र-तट से दूर मछली पकड़ने वाली जलयानों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना; द्विपक्षीय तौर पर सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत समुद्र तट से दूर मछली पकड़ने के आधुनिक जलयानों का अधिग्रहण; संयुक्त उद्यम/विदेशी मत्स्यन जलयानों के पट्ट के अंतर्गत परिष्कृत इलैक्ट्रानिक तथा मत्स्यन औजारों के साथ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयानों के प्रवेश को प्रोत्साहन देना; विविध तथा विशिष्ट मात्स्यिकी संसाधन के संचालन के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विद्यमान जलयानों में सुधार करना, इत्यादि शामिल है ।

बटर ऑयल का आयात

2762. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बटर ऑयल का आयात कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो आयात किए जाने के क्या कारण है तथा आयात के लिए प्राधिकृत की गई एजेंसी का नाम क्या है, और उस देश का नाम क्या है जिसके साथ बटर ऑयल के आयात के लिए सौदा किया गया है ;

(ग) आयातित बटर आयल की कुल मात्रा कितनी है ; और

(घ) इसके आयात पर कुल कितना खर्च होगा और किस समय तक और किस मूल्य पर आम जनता को इस आयातित बटर ऑयल को उपलब्ध कराया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) देश में मुख्य रूप से दुग्ध वसा की कमी पर काबू पाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को चालू वित्त वर्ष के दौरान बटर ऑयल का आयात करने की अनुमति दी है । राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने बटर ऑयल का आयात करने के लिए न्यूजीलैण्ड तथा आस्ट्रेलिया की पार्टियों से संपर्क किया है ।

(ग) और (घ) वर्ष के दौरान अब तक आयात किए गए बटर ऑयल की मात्रा इस प्रकार है :—

महीना	प्राप्त/प्राप्त की जा रही मात्रा	लागत (मी० टन) (अमरीकी डॉलर)
अक्तुबर, 94	250 मी० टन	1600 लागत तथा भाडा
नवम्बर, 94	(क) 250 मी० टन	1600 लागत तथा भाडा
	(ख) 992 मी० टन	1730 लागत सहित भाडा
दिसम्बर, 94	1008 मी० टन	1730 लागत सहित भाडा
	800 मी० टन	1730 लागत सहित भाडा

केवल आवश्यकता पड़ने पर ही और आयात किया जाएगा । अब तक आयात की गई मात्रा बहुत कम है तथा तरल दूध के पुर्नसम्मिश्रण के लिए इसे सहकारी समितियों को उपलब्ध कराया गया है ।

Identification, Modernisation and Extension of Irrigation Projects

2763. SHRI RAHASBIHARI BARIK : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the irrigation projects in Orissa and other States identified for renovation, extension and modernisation during the 7th and 8th plan ;

(b) how far these programmes have been implemented ;

(c) whether it is a fact that there have been serious irregularities in the implementation of the irrigation projects ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) the steps taken to ensure proper implementation of these projects?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) and (b) 95 Extension/Renovation/Modernisation (ERM) Projects have spilled over into VIIIth Plan. Out of these, one project is in Orissa which was taken up in VIth Plan. The State Government has identified 15 ERM Projects for the VIIIth Plan which includes the Project on-going from VIth Plan. All of these, excepting one are scheduled for completion in VIIIth Plan.

(c) to (e) Irrigation is a State subject and as per present policy these are planned, executed and funded by the States out of their own resources.

Loss due to Natural Calamities in Orissa

2764. SHRI RAHASBIHARI BARIK : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have made any assessment on the total loss suffered by the State of Orissa during the current year due to natural calamities like drought, flood etc ;

(b) if so, till which month the assessment has been made and the details thereof ;

(c) to what extent the central Government has helped the State Government of Orissa to meet the challenges ; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) and (b) On the basis of assessment made by the Government of Orissa as on 17th October, 1994, floods during the current south-west monsoon affected a population of 51.71 lakhs in 14197 villages of 25 districts. The floods also claimed 88 human lives and damaged 10735 houses in various parts of the State.

(c) and (d) Under the existing scheme, the State Government undertakes relief and rehabilitation measures in the wake of natural calamities using the corpus of the Calamity Relief Fund. The entire Central share of Calamity Relief Fund for the year 1994-95 amounting to Rs. 29.78 crores has been released to the Government of Orissa.

Inclusion of Representatives from Tamil Nadu in Task Forces and Expert Committee

2765. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government propose to include the representatives from Tamil Nadu in all Task Forces and Expert Committee to be formed by his Ministry;

(b) whether it is a fact that farmers and bidi tobacco growers have been requesting his Ministry to form an Expert Committee to Study and assess the long term impact of anti tobacco legislation ; and

(c) when Government will take steps to examine such aspects of the farmers' problems?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) to (c) There are representations both from tobacco growers' and tobacco industry including bidi tobacco growers' against the proposed legislation of the Ministry of Health & Family Welfare to ban advertisement of tobacco and tobacco products and requests for setting up an Except Committee to study the impact of legislation on tobacco farmers. At present, no such Expert Committee/Task Force is being set-up by this Ministry. Ministry is advising farmers for deversification and switch over to other crops.

Export of Food Items

2766. SHRI RATNA BAHADUR RAI : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) the quantity of rice, dal and sugar produced during the last three years ; and

(b) what are the food items exported during this period and what amount of money was spent thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) The production of rice, dal and sugar